सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 19 SEPTEMBER TO 25 SEPTEMBER 2025 • VOLUME 09 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

"सपनों का आसमान उतना ही नीला दिखता है,
जितनी बार हम गिरकर फिर उठ खड़े होते हैं।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	31°	23°
शनिवार	34°	24°
रविवार	35°	24°
सोमवार	35°	22°
मंगलवार	34°	23°
बुधवार	39°	25°
वीरवार	39°	24°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

अडानी ग्रुप को सेबी से बड़ी राहत

नई दिल्ली. बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए आरोपों के संबंध में अडानी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ मामले का निपटारा किया। सेबी ने अडानी समूह और उसके अरबपति संस्थापक गौतम अडानी को शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए कुछ अनियमितताओं के आरोपों से मुक्त कर दिया है। सेबी ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित दो अलग-अलग आदेशों में कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारतीय समूह ने अपनी सूचीबद्ध इकाइयों में धन भेजने के लिए किसी तथाकथित संबंधित पक्ष का इस्तेमाल किया। अडानी समूह ने जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग द्वारा पहली बार लगाए गए आरोपों का बार-बार खंडन किया था।

हिंडनबर्ग द्वारा की गई नाकामियों के बारे में बात करते हुए गौतम अडानी ने हर गिरावट के बाद और मज़बूती से उभरने के महत्व पर ज़ोर दिया था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, हमने ऐसे नेताओं का एक समूह तैयार किया है जो बार-बार अज्ञात में कदम रखने का साहस रखते हैं। अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करते हुए भी यही उनका साहस दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व का

यही स्वरूप अडानी समूह की पहचान है। हमारी नेतृत्व क्षमता पिछले साल जनवरी में वित्तीय बाज़ार पर हुए हमले के दौरान सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी। यह विदेश से शुरू किया गया एक शॉर्ट-सेलिंग हमला था। यह कोई आम वित्तीय हमला नहीं था। अडानी समूह के अध्यक्ष ने ज़ोर देकर कहा यह हमारी वित्तीय स्थिरता को निशाना बनाकर किया गया दोहरा हमला था और हमें राजनीतिक तूफ़ान में धकेल रहा था। यह एक सोची-समझी चाल थी, जो हमारे अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) के बंद होने से कुछ ही दिन पहले की गई थी और अधिकतम नुकसान पहुँचाने के लिए रची गई थी - और निहित स्वार्थों वाले कुछ मीडिया द्वारा इसे और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

झूठ फैलने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए : अडानी

अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग के लगाए आरोप सेबी की तरफ से खारिज होने के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गौतम अडानी ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि झूठ फैलाने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए। गौतम अडानी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सेबी की विस्तृत जांच के बाद यह साफ हो गया है कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी जो बात

हम हमेशा से कहते आ रहे थे कि हिंडनबर्ग के दावे आधारहीन थे, अब सेबी की गहन जांच के बाद फिर से साबित हो गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को हुए नुकसान पर गौतम अडानी ने कहा कि हमें उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस होता है, जिन्होंने इस फ्रॉड और प्रेरित रिपोर्ट के कारण अपने पैसे गंवाए। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने वालों को अब राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए लिखा कि भारतीय संस्थानों, भारत के लोगों और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग है। उन्होंने सत्यमेव जयते और जय हिंद से अपनी बात का समापन किया।

ऑनलाइन गेमिंग के नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू

नई दिल्ली. केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। वैष्णव ने कहा कि हमने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की है और कानून पारित होने के बाद एक बार फिर हमने उनके साथ बातचीत की है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने बैंकों और अन्य हितधारकों से भी परामर्श किया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार का

दृष्टिकोण बहुत ही परामर्शात्मक बना हुआ है और कार्यान्वयन से पहले उद्योग के साथ एक और दौर की चर्चा की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पूर्व-कार्यक्रम समारोह में बोलते हुए कहा कि हमने इसमें व्यावहारिक रूप से हर संभव हितधारक के साथ बातचीत की है और हमने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। ये नियम पहली अक्टूबर से लागू होंगे और उससे पहले हम उद्योग के साथ एक और दौर की चर्चा करेंगे और अगर हमें और समय की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से अधिक परामर्शात्मक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे जो हमारा मानक दृष्टिकोण है।

छह नशा तस्कर 9 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/अमृतसर

सीमा पार चल रहे नार्को-आतंक नेटवर्कों विरुद्ध बड़ी सफलता दर्ज करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने छह नशा तस्करों को 9.066 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार करके दो और नशा तस्करी गिरोहों का पर्दाफ़ाश किया है। यह जानकारी पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने वीरवार को यहाँ दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के गाँव काले घनूपुर के हनी (18), अमृतसर के जंडियाला गुरु के परमदीप सिंह उर्फ़ पारस (18), अमृतसर के जंडियाला गुरु के हरविंदर सिंह उर्फ़ हिंदा (19), अमृतसर के गाँव डांडे के गुरप्रीत सिंह उर्फ़ गोपी (25), तरनतारन के गाँव ढाला की जसबीर कौर (40) और तरनतारन के गाँव हवेलियां की कुलविंदर कौर (54) के रूप में हुई है। यह कार्रवाई अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस गुरप्रीत सिंह भुल्लर द्वारा मोगा स्थित जगप्रीत सिंह उर्फ़ जग्गा द्वारा चलाए जा रहे नशा तस्करी सिंडिकेट के मुख्य सहयोगी यासीन मुहम्मद को 7.1 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार करने के एक दिन बाद अमल में लाई गई है।

फर्जी जीएसटी बिलिंग घोटाले में पिता-पुत्र गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** लुधियाना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, लुधियाना के अधिकारियों ने एक विशिष्ट सूचना के आधार पर 16 सितंबर को लुधियाना में कई तलाशी अभियान चलाकर 455 करोड़ रुपये मूल्य के एक बड़े फर्जी जीएसटी चालान रैकेट का पर्दाफाश किया। मेसर्स वासु मल्टीमेटल्स, मेसर्स एसवीएम मल्टीमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंगॉटैस्टिक एलएलपी नामक तीन संबंधित फर्में फर्जी चालान प्राप्त करने और अपनी जीएसटी देनदारियों को समायोजित करने के लिए 69.41 करोड़ रुपये के अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का उपयोग करने में शामिल थीं, जिससे सरकारी राजस्व में भारी कमी आई। तलाशी अभियान के बाद इन फर्मों का संचालन और नियंत्रण करने वाले दो व्यक्तियों (पिता-पुत्र की जोड़ी) को केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नेटवर्क की पूरी सीमा का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य संस्थाओं की पहचान करने के लिए जाँच जारी है।

भगवंत मान सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने राज्य में बाढ़ प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए 26 से 29 सितम्बर, 2025 तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय किया है। यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष सत्र हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित नियमों में कई जनहितकारी संशोधन प्रस्तुत करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के मुआवज़े संबंधी नए कानून भी सदन में पेश किए जाएंगे और मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ से हुई भारी तबाही का ज़िक्र करते हुए कहा कि इससे 2,300 से अधिक गांव डूब गए, 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और पाँच लाख एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि इस आपदा में 56 लोगों की जान चली गई और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 3,200 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त हुए, 19 कॉलेज मलबे में तब्दील हो गए, 1,400 क्लीनिक और अस्पताल खंडहर बन गए, 8,500 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो गईं और 2,500 पुल ढह गए।

मोदी ने की कार्की से बात, कहा- नेपाल में शांति बहाली को भारत आपके साथ

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की और बातचीत को गर्मजोशीपूर्ण और रचनात्मक बताया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और पड़ोसी देश में शांति और स्थिरता बहाल करने में भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौतीपूर्ण समय में नेपाल के साथ खड़े रहने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और 19 सितंबर को पड़ने वाले नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कार्की और नेपाल की जनता को हार्दिक बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए घनिष्ठतापूर्वक कार्य जारी रखने के प्रति भारत की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने नेपाल में शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में नेपाल के प्रयासों के लिए भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक

शुभकामनाएँ दीं। इससे पहले 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कार्की को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी थी और उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण" बताया था। मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल साझा इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े घनिष्ठ मित्र रहे हैं और नई दिल्ली इस संक्रमण काल में पड़ोसी देश के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से कार्की को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

देश के जेन-जी संविधान को बचाएंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं : राहुल

नई दिल्ली. चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाने के बाद विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक महत्वपूर्ण एक्स पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन-जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा

हूं। जय हिंद! इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों' को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हालाँकि कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि तथाकथित 'हाइड्रोजन बम' का अभी भी अंदेशा है। उन्होंने दावा किया कि 'कुछ खास लोग' उन अल्पसंख्यक समूहों के वोटों को व्यवस्थित रूप से काट रहे हैं जो विशेष रूप से कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं युवाओं और जनता को इस बात का स्पष्ट सबूत दिखाने जा रहा हूँ कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किया है। मैं आपको वोट जोड़ने, हटाने के तरीके भी दिखाऊँगा और यह भी दिखाऊँगा कि यह कैसे किया जाता है। कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 6 हज़ार वोट हटाए गए हैं। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उसी राज्य के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी फर्जी वोट पड़े थे।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया निराधार और गलत

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों को 'गलत और निराधार' करार देते हुए खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी वोट को ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति द्वारा हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है। आयोग ने आगे रेखांकित किया कि मतदाता सूची में किसी भी बदलाव से पहले उचित प्रक्रिया अनिवार्य है। उसने आगे कहा कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नाम नहीं हटाए जा सकते।' कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित रूप से नाम हटाए जाने के विवाद पर बोलते हुए, चुनाव आयोग ने बताया कि पिछले साल आयोग ने ही विसंगतियों को चिन्हित किया था। बयान में कहा गया है कि 2023 में, अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए ईसीआई के प्राधिकार द्वारा स्वयं एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर भी स्पष्टीकरण दिया। रिकॉर्ड के अनुसार, अलंद विधानसभा क्षेत्र 2018 में सुभाष गुट्टेदार (भाजपा) और 2023 में बीआर पाटिल ने जीता था। इससे पहले, चुनाव आयोग के सूत्रों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर सीधे निशाना साधने वाली राहुल गांधी की टिप्पणी को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया था और ज़ोर देकर कहा था कि उन्होंने केवल छह महीने पहले ही कार्यभार संभाला है और पिछले साल सामने आई कथित अनियमितताओं के लिए उन्हें ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना : मोदी का अंदाज

जालंधर ब्रीज. नरेंद्र मोदी की यात्रा के मूल में एक विशेष आदत: अनवरत अवलोकन निहित है। वह प्रत्येक मुलाकात को विचारों के स्रोत के रूप में देखते हैं, चाहे वह सामान्य बातचीत हो या विदेश यात्रा। लेकिन इन्हें नवीनता या अकादमिक विचार मानने वाले अनेक लोगों के विपरीत, मोदी इनमें से प्रत्येक विचार को संभावित समस्या के मूल कारण के आधार के तौर पर परखते हैं और फिर उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल समाधान में ढालते हैं। जिज्ञासा, विश्लेषण और प्रभावी क्रियान्वयन के इसी मिश्रण ने उन्हें जमीनी स्तर के आयोजक से एक वैश्विक राजनेता के रूप में स्थापित किया है।

वास्तव में, मोदी के लिए सीखना कभी उम्र का मोहताज नहीं रहा। बचपन से ही, उनमें सहज जिज्ञासा थी और वे विविध कहानियों और अनुभवों को आत्मसात करते और तलाशते थे। जीवन भर उनका यही विश्वास रहा है कि जिज्ञासा हर स्तर पर को सीखने को बढ़ावा देती है। यहाँ तक कि उनकी जिम्मेदारियाँ जब क्षेत्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय पद तक बढ़ गई, इसके बावजूद, ऐसी नियमित मुलाकाते उनके मन में विचारों को जन्म देती रहीं और छोटी-छोटी बातें सीख में बदल गईं, जो वर्षों बाद, ऐन कार्रवाई करने का समय आने पर ही फिर से उजागर हुईं।

किशोरावस्था में, ज्ञान की इसी ललक ने उनकी यात्रा का आगाज़ किया। पहले-पहल आध्यात्मिक साधक के रूप में और बाद में एक समर्पित संघ प्रचारक के रूप में उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और ऐसे अनुभव बटोरे, जिन्होंने दुनिया को देखने-समझने की उनकी दृष्टि को आकार दिया। हर बातचीत उनके लिए कुछ नया सीखने का अवसर थी। लेकिन जो बात उन्हें दूसरों से

हसमुख अधिया
(सेवानिवृत्त सचिव, वित्त एवं राजस्व, भारत सरकार)

जुदा करती है, वह यह है कि यह सूझबूझ केवल सैद्धांतिक नहीं रही; अवसर पाते ही, उन्होंने इसे क्रियान्वित किया। हालाँकि, समस्या-समाधान की यह कला अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से सामने आती रही। उदाहरण के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान, उन्होंने देखा कि कर्मचारी संगमरमर के ठंडे फर्श पर नंगे पाँव काम कर रहे थे और उन्होंने तुरंत उन कर्मचारियों के लिए जूट की चप्पलों का प्रबंध कर दिया, यह एक आसान उपाय था, जो सर्दी और आने वाली गर्मी, दोनों के लिए कारगर रहा। एक अन्य घटना में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जापान की अपनी यात्रा के बाद, उन्होंने स्पर्शनीय मार्गचिन्ह (उभरी हुई सतह) की अवधारणा शुरु की। दृष्टिबाधित लोगों के लाभ के लिए उन्होंने इसे अहमदाबाद में लागू करने पर ज़ोर दिया। ये संकेत उनकी एक अनवरत आदत को जाहिर करते हैं: अनदेखा कर दी गई बारीकियों को दैनिक जीवन को आसान बनाने वाले व्यावहारिक सुधारों में बदलना।

उनके कुछ विचार बीते दशकों की याद दिलाते हैं। 1993 में लॉस एंजिल्स की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने फाइनेंशियल हाई-राइजिज के समूहों का अध्ययन किया; वर्षों बाद, उन्हीं विचारों ने गुजरात में गिफ्ट सिटी को भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को केंद्रीकृत करने के केंद्र के रूप में प्रेरित किया। इसी जिज्ञासा ने अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट को आकार दिया, जहाँ उन्होंने अधिकारियों से दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करवाया, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि अंतिम डिज़ाइन स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित रहे। उनके अनुसार, ग्लोबल मॉडल तभी मायने रखते हैं, जब उन्हें पहले स्थानीय समुदायों की सेवा के लिए अनुकूलित किया जा सके। इस पद्धति में, कोई भी अवलोकन कभी भी सराहना किए योग्य अलग-थलग विचार नहीं होता, बल्कि यह एक रिसोर्स बैंक की तरह होता है, जो परिस्थितियों के अनुकूल होने पर लौटकर आता है, और संग्रहीत विचारों को विशाल परियोजनाओं में परिवर्तित कर देता है।

2002 में, कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मोदी ने आपदा से निपटने में इस पद्धति को अपनाया। उन्होंने नियमित नौकरशाही मॉडलों को नकारते हुए अपनी टीम को जापान के कोबे भूकंप प्रबंधन का अध्ययन करने और उसके योजनाकारों से संपर्क करने का निर्देश दिया। लेकिन उनका विचार स्पष्ट था: मॉडलों को पूरी तरह से आयातित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, इन जानकारियों को गुजरात के लिए तत्काल आवश्यकता वाले समाधानों जैसे भूकंपरोधी आवास, सुरक्षित निर्माण पद्धतियों और सामुदायिक भागीदारी- में ढाला गया। भारत में यह पुनर्वास के लिए एक मानक बन गया, जिसने दिखाया कि कैसे एक संकट अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को भारतीय पहल के साथ मिलाने का परीक्षण स्थल बन सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने इसी क्रम को जारी रखा, दक्षिण कोरिया में नदी-सफाई परियोजनाओं का दौरा इसी इरादे से किया, कि उनसे प्राप्त सबक को नमामि गंगे में लागू किया जा सके। भारत के भीतर से उभरने वाले विचारों के प्रति भी उन्होंने उतना ही उत्साह दिखाया है। इसका उल्लेखनीय उदाहरण नैनो यूरिया है, जो एक युवा वैज्ञानिक द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए सुझाव से उपजा नवाचार है।

ये कहानियाँ मिलकर मोदी के जीवन के एक अनवरत सूत्र को उजागर करती हैं। मंदिर में मामूली प्रतीत होने वाली असुविधा को दूर करने से लेकर, एक आधुनिक शहर की रूपरेखा तैयार करने, किसी तबाह क्षेत्र के पुनर्निर्माण या किसी क्रांतिकारी उर्वरक को अपनाने तक, उनकी प्रक्रिया एक समान ही रही है: स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना, लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करना और उसे पूरा करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना। "आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:" (प्रत्येक दिशा से कल्याणकारी विचार हमारी ओर आएँ) के भारतीय दर्शन का पालन करते हुए, मोदी हर यात्रा और संवाद से सक्रिय रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और भारत को आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करने का दृढ़तापूर्वक प्रयास करते हैं। अंततः, उनका हर विचार लोगों के लिए होता है, उनके जीवन और विकसित भारत की उनकी आकांक्षाओं में निहित होता है।

-लेखक एक आईएएस अधिकारी हैं, जो भारत के वित्त एवं राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

होटल रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जानकर चौंक जाएंगे!

Travelling होटल में मौजूद कई चीजें ऐसी हैं, जो ना कभी बदली जाती हैं और ना ही साफ की जाती हैं। ऐसे में इन्हें छूने के बाद आपको हाथ जरूर धो लेने चाहिए, वरना बैक्टीरिया फैलने का खतरा हो सकता है।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

किसी ट्रिप पर जाएं या बाहर कहीं रुकना पड़ जाए, तो होटल में ही ठहरना पड़ता है। खाने-पीने और सेफ्टी के लिहाज से एक अच्छा होटल काफी सहूलियत भरा होता है। होटल में आमतौर पर कई चीजें मौजूद होती हैं और हम ये भी जानते हैं कि कई चीजें हमसे पहले किसी और ने भी इस्तेमाल की होंगी। इनमें से कई चीजें तो इतनी ज्यादा गंदी होती हैं कि उन्हें टच भी नहीं करना चाहिए। जी हां, होटल में मौजूद कई चीजें ऐसी हैं, जो ना कभी बदली जाती हैं और ना ही साफ की जाती हैं। ऐसे में इन्हें छूने के बाद आपको हाथ जरूर धो लेने चाहिए, वरना बैक्टीरिया फैलने का खतरा हो सकता है।

होटल रुम में मौजूद टेलीफोन

होटल के कमरे में आमतौर पर एक टेलीफोन मौजूद होता है। अगर आपको रिसेप्शनिस्ट से कोई मदद चाहिए, तो इसका इस्तेमाल करना होता है। हालांकि बता दें ये टेलीफोन सालों से ऐसे ही रखा रहता है और हर दूसरा गेस्ट इनका इस्तेमाल करता है। ऐसे में ये होटल में मौजूद सबसे गंदी चीजों में से एक होता है और इसपर ढेर सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं।

बैक्टीरिया से भरा होता है रिमोट

होटल रूम में रखा टीवी और एसी का रिमोट बहुत ज्यादा गंदा होता है। इसे हर दूसरा गेस्ट इस्तेमाल करता है और जाहिर है इसे कभी साफ भी नहीं किया जाता। ऐसे में खाना खाते समय आपको ये रिमोट बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे छूते भी हैं, तो बाद में हैंड वॉश जरूर कर लें।

कमरे में लगे स्विच बोर्ड

होटल के कमरे में लगे स्विच बोर्ड भी सबसे गंदी जगहों में से एक होते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और जाहिर है कोई हाथ धो कर तो इसे टच करता नहीं है। वहीं होटल स्टाफ भी इसे क्लीन नहीं करते। इस वजह से इसपर बैक्टीरिया का ढेर जमा होता है। कोई बीमारी नहीं चाहते हैं, तो इनका इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ जरूर धो लें।

दरवाजे के हैंडल

मेन दरवाजा हो या बाथरूम के डोर का हैंडल, इसपर सबसे ज्यादा जर्म्स लगे होते हैं। ये भले ही आपको शाइनी दिखे लेकिन होता काफी ज्यादा गंदा है। इसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं और होटल स्टाफ इसे साफ करने की जहमत भी नहीं उठाता। इसलिए जब भी ये दूर हैंडल टच करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें।

अलमारी और स्टोरेज

होटल में रखी अलमारी और स्टोरेज बॉक्स भी काफी गंदे होते हैं। हर कोई यहां अपना सामान रखता है, जिसे दोबारा साफ नहीं किया जाता है। ऐसे में यहां काफी बैक्टीरिया और जर्म्स हो सकते हैं। आपको अपना सामान यहां रखते हुए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इन जगहों को टच करने के बाद आपको अपने हाथ भी जरूर धो लेने चाहिए।

EXPERT TIPS

घर का काम करती हैं, फिर भी एक्सरसाइज की जरूरत है क्या? हेल्थ एक्सपर्ट से जानें

ज्यादातर महिलाओं को ये लगता है कि वर्कआउट की भला इन्हें जरूरत ही क्या है। घर का सारा काम तो ये करती ही हैं, उसी में एक्सरसाइज भी हो जाती है। आइए जानते हैं इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स की क्या राय है।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

घर में सभी की सेहत का ध्यान रखने वाली महिलाएं अक्सर अपनी सेहत को ले कर बड़ी लापरवाह होती हैं। इनके खानपान की टाइमिंग ठीक नहीं होती, अपने लिए स्पेशल डाइट ये बनाती नहीं और वर्कआउट का टाइम निकालने का इन्हें ख्याल भी नहीं आता। ज्यादातर महिलाओं को ये लगता है कि वर्कआउट की भला इन्हें जरूरत ही क्या है। घर का सारा काम तो ये करती ही हैं, उसी में एक्सरसाइज भी हो जाती है। क्या आप भी कुछ ऐसा ही मानती हैं? तो आइए जानते हैं इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स की क्या राय है।

क्या घर का काम और एक्सरसाइज बराबर हैं?

ज्यादातर भारतीय महिलाएं अपने लिए एक्साइज का समय निकालती ही नहीं हैं। उनका मानना होता है कि घर का काम करने में ही उनकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो घर का काम कोई एक्सरसाइज नहीं है। सही मायनों में एक्सरसाइज वो होती हैं, जहां आप आधा-एक घंटा लगातार कोई फिजिकल एक्टिविटी करती हैं। इसमें वॉकिंग, योग, प्राणायाम या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी शामिल हो सकती है।

घर के काम और एक्सरसाइज में अंतर

घर के काम जैसे झाड़ू-पोछा, कपड़े या बर्तन धोना भी एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी हैं, जिनमें आपका शरीर एक्टिव होता है। ये थोड़ी बहुत कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बॉडी को फिट और हेल्दी बनाए रखने में इनका रोल बहुत कम है। घर के काम की जगह एक्सरसाइज में इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है और आप लगातार कुछ समय के लिए वो करती हैं। इससे हार्ट हेल्थ, स्टैमिना, बोन स्ट्रेंथ और वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप घर के काम को अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनाए रख सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें। हफ्ते में कम से कम तीन दिन एक्सरसाइज को जरूर दें। ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, तो वॉक या हल्के योग से शुरुआत करें। इसके अलावा आपको अपने खानपान का ध्यान रखने की भी जरूरत है। जब खुद का ध्यान रखेंगी और खुद से प्यार करेंगी, तभी दूसरों के लिए भी कर पाएंगी।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

हर बार कुरकुरी और टेस्टी बनेगी भिंडी की सब्जी, बस फॉलो करें ये 5 टिप्स

भिंडी बनाते समय उसमें से म्यकिलेज नामक पदार्थ निकलता है, जिस वजह से भिंडी काफी चिपचिपी सी हो जाती है। यहां हम आपके लिए कछ ऐसी टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप हर बार कुरकुरी भिंडी बना सकती हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

भिंडी उन सब्जियों में से एक है, जिसका स्वाद भी सभी को पसंद आता है और इसमें भरपूर पोषण भी होता है।

भिंडी से स्वादिष्ट सूखी सब्जी, भरवां भिंडी, भिंडी दो प्याजा जैसी कई डिशेज बनाई जाती हैं। हालांकि इन सबमें एक कॉमन समस्या आती है, वो हैं भिंडी की चिपचिपाहट।

भिंडी बनाते समय उसमें से म्यूकिलेज नामक पदार्थ निकलता है, जिस वजह से भिंडी काफी चिपचिपी सी हो जाती है। ये खाने में भी अच्छी नहीं लगती।

भिंडी का मजा तो तब है, जब इसमें हल्का कुरकुरापन बरकरार रहे। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसी ही सिंपल टिप्स ले कर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप हर बार कुरकुरी भिंडी बना सकती हैं।

भिंडी हमेशा बनेगी कुरकुरी

- भिंडी में म्यूकिलेज नाम का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, जो इसे चिपचिपा बनाता है। भिंडी बनाते समय चिपचिपी न हो, इसके लिए साबुत भिंडी को अच्छी तरह से धोकर पहले पानी सुखा लें। पानी को सुखाने के लिए टिश्यू पेपर की मदद लें। कभी भी भिंडी को काटने के बाद धोने की गलती न करें।
- जब भी आप सब्जी बनाने के लिए भिंडी काटें, तो उन्हें छोटे आकार में काटने की बजाय लंबे टुकड़ों में काटें। लंबे टुकड़ों में काटने से भिंडी अधिक क्रिस्पी बनेगी। बेहतर होगा कि आप भिंडी की एक फली को अधिकतम दो-तीन टुकड़ों में ही काटें।
- भिंडी को अच्छी तरह से भूनकर भी आप इसकी चिपचिपाहट दूर कर सकती हैं। यह एक असरदार तरीका है। इसके लिए कड़ाही में तेल गर्म करने के बाद भिंडी के बड़े टुकड़ों को आठ से दस मिनट तक भूनें। इसके बाद ही किसी भी तरह की अन्य सामग्री को कड़ाही में डालें।
- भिंडी की सब्जी बनाते वक्त उसमें शुरुआत में नमक डालने की गलती न करें। जब सब्जी पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब उसमें स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं। मध्यम आंच पर तीन से चार मिनट तक सब्जी को पकाएं और गैस ऑफ कर दें।
- भिंडी की सब्जी बनाएं तो अंत में इसमें थोड़ा नीबू का रस मिला दें। दही भी चिपचिपेपन की इस समस्या से छुटकारा देगा। इमली के जूस या अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सूखी सब्जी में अमचूर पाउडर या नीबू का रस डालें और गीली सब्जी में इमली का जूस या दही डालें।

बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है स्क्रीन

जालंधर ब्रीज (फीचर) . यह सच है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर इसका नकारात्मक असर दिख रहा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60% से अधिक बच्चे रोज़ाना 2-4 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं, जबकि WHO केवल 1 घंटे की सलाह देता है। 3,624 बच्चों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि स्क्रीन की अधिकता से मोटापा, नींद की समस्या, चिंता, एकाग्रता की कमी और सामाजिक कौशल में गिरावट जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। इसलिए बच्चों की स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण बेहद ज़रूरी है।

नियम बनाएं, कड़ाई से लागू करें

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को वीडियो चैटिंग के अलावा, मीडिया के इस्तेमाल से भी दूर रहने की सलाह देता है। यदि 18 से 24 महीने के बच्चे डिजिटल मीडिया से परिचित हो जाते हैं, तो माता-पिता को यह ध्यान रखना होगा कि कंटेंट की गुणवत्ता अच्छी हो। ध्यान रखें कि बच्चे अकेले में स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्क्रीन टाइम को मैनेज करने का तरीका भी बदलें।

बच्चों के साथ समय बिताएं

बाल मनोविशेषज्ञ सीमा बत्रा बताती हैं, 'यदि बच्चे स्क्रीन पर अधिक समय बिता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिता रही हैं। बच्चे के साथ बातचीत करने और खेलने के लिए समय निकालें। उन्हें बाहरी दुनिया के प्रति सजग और जागरूक बनाएं। अपने बच्चे के दोस्तों को जानने का प्रयास करें। आपका बच्चा उनके साथ किस तरह की बातें करता है और उनके साथ क्या-क्या करता है, यह भी जानने का प्रयास करें।'

अपने स्तर पर करें जांच-पड़ताल

बच्चे के संपर्क में आने वाले हर तरह के कंटेंट की गुणवत्ता पर नजर रखें। अपने बच्चे को किसी तरह के वर्चुअल प्रोग्राम, साइट, गेम खेलने और ऐप्स देखने देने की अनुमति देने से पहले अपने स्तर पर उनकी जांच-पड़ताल कर लें। 'कॉमन सेंस मीडिया' जैसे संगठन बच्चे की उम्र के लिए उपयुक्त प्रोग्रामिंग रेटिंग और समीक्षाएं देते हैं। बच्चे के उनका इस्तेमाल करने से पहले आप भी साथ में देखने बैठें या खेलें या इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर भी बच्चे के लिए ऐसे विकल्प खोजें, जो उन्हें व्यस्त रखें न कि ऐसे विकल्प, जिनमें बस स्क्रीन पर स्वाइप करना या उन्हें लगातार निहारते रहना शामिल हो। **-शेष अगले अंक में...**

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

बच्चों की कमजोर नजर को तेज कर सकता है डॉक्टर का बताया ये नुस्खा

Health बहुत ही छोटी उम्र में जिन बच्चों को नजर का चश्मा लग जाता है और नजरों से देखने में दिक्कत होती है। उनके लिए डॉक्टर सुभाष गोयल का बताया ये घरेलू नुस्खा असर दिखा सकता है।

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

बच्चे आजकल कमजोर नजर का शिकार हो रहे हैं। घंटों मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पर बिताने के साथ ही उनकी आउटडोर एक्टीविटी कम हो गई है। जिससे नजरों को दूर तक नेचुरल रोशनी में देखने की आदत खत्म हो जाती है। वहीं पढ़ने-लिखने के साथ आंखों को रेस्ट ना देने की वजह से कम उम्र में ही बच्चों आई मसल्स वीक होने लगती है। खानपान में न्यूट्रिशन की कमी और भी ज्यादा इस वीक मसल्स को बढ़ा देता है। जिसकी वजह से नजरों का कमजोर हो जाना काफी आम बात हो गई है। लेकिन बच्चों की कमजोर हो रही नजर को सही करने के लिए डॉक्टर सुभाष गोयल ने नेचुरल तरीका बताया है।

डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया नेचुरल तरीका

सुभाष गोयल नेचुरल उपचार बताने को लेकर फेमस है। कई सारे शोज में उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है और कम उम्र में नजर का चश्मा लग जाता है। उन्हें ये उपाय करने से राहत मिलती है। कम उम्र में कमजोर हो चुकी नजर को ठीक करने में मदद मिलती है। और उम्र बढ़ने के साथ पावर बढ़ने की समस्या खत्म हो जाती है।

नारियल और देसी घी मिलाकर लगाएं

100 ग्राम शुद्ध देसी घी में 50 ग्राम शुद्ध नारियल का तेल मिलाकर रख लें। इस मिक्सचर को बच्चों की नाभि और अंडरआर्म्स में लगाएं। रात को सोने से पहले और सुबह नहाने से पहले दो बार इस मिक्सचर को लगाने से आंखों की नजर को तेज होने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में नाभि को प्राण कहा गया है। यहां पर कई सारी नसें होती है सीधा दिमाग तक जाती है। जब घी और नारियल के तेल के मिक्सचर को लगाते हैं तो इससे दिमाग के पीछे का हिस्सा मेडुला एक्टिव होता है और बच्चों में कमजोर याददाश्त बढ़ाने के साथ आंखों की नजर को तेज करने में मदद मिलती है।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

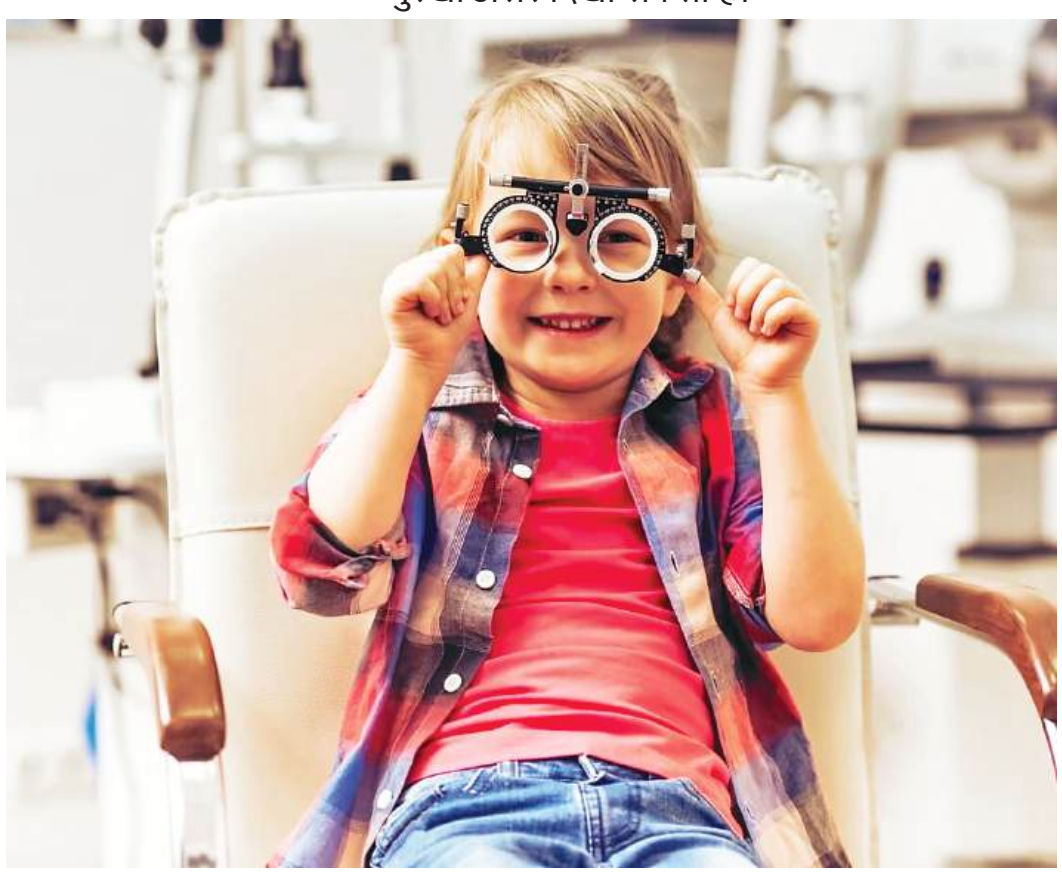

मोदी का ट्रैम्पोलिन - क्या हम छलांग लगा पाएंगे?

पिछली शताब्दियों में मानवता ने जो चुनाव किए हैं, वे हमें संकट की कगार पर लेकर आए हैं। जिस तरह से हमने अपनी अर्थव्यवस्थाओं, अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी, अपनी शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था, अपने युवाओं और अगली पीढ़ी के पालन-पोषण को संभाला है, उसने हमें हमें इस अस्थिर स्थिति तक पहुंचा दिया और दुनिया को संकट की दहलीज पर ला खड़ा किया है। आज अलग-अलग जगहों पर युद्ध, अस्थिर आर्थिक ढांचे, तेज़ी से बिगड़ती पारिस्थितिकी और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, मानसिक स्वास्थ्य महामारी और नशे की लत जैसी समस्याएं, ये सब इसके प्रमाण हैं।

इसका मतलब विनाश और निराशा की तस्वीर पेश करना नहीं है। बदलाव की स्थिति, दरअसल संभावनाओं की स्थिति होती है। आज जो फैसले हम करेंगे, वे हमें या तो बड़े परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं या फिर पतन की ओर धकेल सकते हैं। 8.5 अरब की आबादी के साथ हम एक भारी-भरकम मानव जाति हैं, लेकिन अभी तक उस चेतना के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जहां हम एकजुट होकर सामूहिक निर्णय ले सकें।

हम सरकारों, क़ानूनों और नेतृत्व पर भरोसा करते हैं कि वे पूरी दुनिया को दिशा दें। ऐसे समय में यह बहुत अहम है कि हम अपने लिए किस तरह का नेतृत्व चुनते हैं। अगर हम पृथ्वी का एक टिकाऊ और सुंदर भविष्य चाहते हैं, तो हमें 'वसुधैव कुटुम्बकम' के आदर्श को सही मायने में अपनाना होगा। यह उपयुक्त है कि भारत, जिसने हमेशा सबको जोड़कर रखने की भावना को महत्व दिया है, ने नरेंद्र मोदी जैसे नेता को चुना है, जो इन मूल्यों को गहराई से मानते हैं। कई मायनों में भारत ने ऐसा नेतृत्व सामने रखा है जो उसकी आत्मा, उसकी संस्कृति और संस्कारों से मेल खाता है। यह बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि समावेशिता सही रास्ता लगती है, बल्कि इसलिए कि आने वाले समय में समावेशिता ही एकमात्र रास्ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बार-बार दुनिया के सामने एक अधिक समावेशी और सहयोगी मानवता का रास्ता दिखाया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने की पहल हो, ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की भूमिका, 'वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड' जैसी विशाल नवीकरणीय ऊर्जा योजना, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति, संकट के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बनना, या फिर महामारी के दौरान 96 देशों को मानवीय सहायता देना, इन सबमें भारत ने यह साबित किया है कि असली मायने काम में होते हैं, और हम छोटे-छोटे निजी लाभ की अपेक्षा मानवता को अधिक महत्व देते हैं।

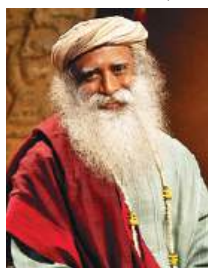

सद्गुरु जग्गी वासुदेव
(धर्म गुरु)

समावेशिता का यह गुण नरेंद्र भाई की नेतृत्व शैली में भी स्पष्ट दिखाई देता है। 'मन की बात' पहल शासन की विशाल व्यवस्था में भले ही एक छोटा हिस्सा लगे, लेकिन इसका संदेश गहरा है। आम नागरिक से सीधा संवाद करके वे उनकी कहानियों, संघर्षों और योगदान को पहचानते और सम्मानित करते हैं। यही जुड़ाव उन्हें ज़मीन से जोड़े रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनकी नीतियां जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

मैं योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में उनकी भूमिका की गहराई से सराहना करता हूं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करवा कर उन्होंने योग के प्रति दुनिया में अद्भुत रुचि जगाई है और यह बताया है कि योग मनुष्य के जीवन में कितनी भलाई ला सकता है। आज के समय में यह और भी जरूरी है, क्योंकि योग की विधियां मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से निपटने का सबसे असरदार उपाय हैं। हर इंसान के लिए यह आवश्यक है कि वह रोज़ कम से कम कुछ मिनट योग या ध्यान को अपनाए, ताकि अपने भीतर स्थिरता और विकास का मजबूत आधार बना सके।

भारत का सभ्यता-राज्य आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वह अपनी असली क्षमता को पहचानकर एक गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ सकता है। अब तक हमने अपनी आर्थिक प्रगति में अभूतपूर्व कार्य और प्रगति देखी है, बुनियादी ढाँचे, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तेजी देखी है। साथ ही, हम आत्मनिर्भरता, भू-राजनीतिक लचीलेपन और शक्ति की दिशा में अपनी नीतियों के कुशल संचालन के भी साक्षी रहे हैं।

हालांकि, एक राष्ट्र के रूप में हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। आने वाली पीढ़ी का सही मार्गदर्शन और पोषण हमारे विकास की कुंजी है। हम नहीं चाहते कि भारत की बढ़ती युवा आबादी इस सुनहरे अवसर को खो दे।

अब समय आ गया है कि हम समाजवाद के अधूरे आदर्शों की आखिरी बेड़ियां तोड़ दें, जिन्होंने पिछले दशकों को जकड़ रखा था, और भारत के नागरिकों को अपने भविष्य के निर्माता बनने के लिए आमंत्रित करें। बुनियादी ढांचे से लेकर ए आई तक, व्यापार से लेकर रक्षा तक, शिक्षा से लेकर उद्योग तक, हमें जनता को इसे सुपरसोनिक गति से आगे बढ़ाने का काम सौंपना होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान शासन द्वारा यह विश्वास वास्तव में प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन असली परीक्षा लोगों द्वारा इस विश्वास को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने और अपनी क्षमता साबित करने की है।

भारत में न केवल अपने सच्चे गौरव के युग में प्रवेश करने की क्षमता है, बल्कि मानवता को उस युग में ले जाने की भी क्षमता है। हमारे पास एक योग्य, साहसी और निस्वार्थ व्यक्ति है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्र केवल ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोग ही उसका असली रूप होते हैं। यह भारत के नागरिकों पर निर्भर है कि वे सुशासन और अवसर के मंच का उपयोग करके अपने इच्छित स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें।

-आइए, इसे साकार करें!

मोदी का शासन : गुजरात मॉडल से भारतीय मॉडल तक

जालंधर ब्रीज : लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने वाले बहुत ही कम नेताओं ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री का दायित्व भी संभाला है। देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री 'राष्ट्रीय' स्तर के नेता रहे हैं और उनके पास संघीय स्तर पर काम करने का अनुभव बहुत ही कम रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इसके चंद अपवादों में से एक हैं।

डॉ. मनसुख एल मांडविया
(केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री)

जब नरेन्द्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो वे अपने साथ गुजरात में एक दशक के राज्य-स्तरीय शासन से विकसित हुए कामकाज के एक नए दर्शन को लेकर आए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इस बात को बारीकी से देखा कि योजनाएं अंतिम छोर पर क्यों विफल या सफल होती हैं और फिर एक ऐसे दृष्टिकोण को परिष्कृत किया जिसने उन्हें शासन के केन्द्र में महज नीति-निर्माण के बजाय क्रियान्वयन को रखने वाला पहला प्रधानमंत्री बनाया। बिजली से लेकर बैंकिंग और कल्याण से लेकर बुनियादी ढांचे के मामले में, इस दर्शन ने तब से आज तक भारतीय राज्य द्वारा अपने नागरिकों की सेवा करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया है।

अनुभव के आधार पर विकसित क्रियान्वयन : नीतिगत केन्द्रबिंदु के रूप में क्रियान्वयन में श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ विश्वास को, बिजली क्षेत्र से संबंधित उनके दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। गुजरात में, उन्होंने देखा कि गांवों में खंभे और लाइनें तो हैं, लेकिन वास्तव में बिजली नदारद है। इसका समाधान उन्होंने ज्योतिग्राम योजना के रूप में निकाला, जिसके तहत फीडरों को अलग किया गया ताकि घरों को 24 घंटे बिजली मिल सके और खेतों को बिजली का एक निश्चित हिस्सा मिल सके। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इस योजना के जरिए 18,374 गांवों को भरोसेमंद तरीके से बिजली उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2023 तक आते - आते, बिजली की यही आपूर्ति सामूहिक रूप से 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करने वाले देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की रीढ़ बन गई।

बैंकिंग क्षेत्र में भी इसी सिद्धांत को फिर से दोहराया गया। कागजों में तो ग्रामीण परिवारों के बैंक में खाते थे, लेकिन व्यवहार में वे निष्क्रिय थे। जन-धन ने इस स्थिति को बदल दिया। आधार और मोबाइल फोन को व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़कर, एक कमजोर पड़ी व्यवस्था को सीधे धन हस्तांतरण की बुनियाद बना दिया गया। इससे धन बिना किसी बिचौलिए के नागरिकों के हाथों में पहुंचा, बर्बादी पर लगाम लगी और सरकारी खजाने को भारी रकम की बचत हुई।

इसके बाद आवास क्षेत्र की बारी आई। प्रधानमंत्री आवास योजना ने भुगतान को निर्माण कार्यों से जोड़ा, उनकी निगरानी के लिए जियो-टैगिंग का इस्तेमाल किया और बेहतर डिजाइन पर जोर दिया। पिछली सरकारों के अधूरे घरों के उद्घाटन के चलन को पलटते हुए, पहली बार लाभार्थियों को पूरी तरह निर्मित और रहने लायक घर मिले।

जीएसटी 2.0 : जनता के प्रति जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक

जालंधर ब्रीज : सरकार ने इनकम टैक्स में राहत देने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में भी सबसे बड़ा सुधार करते हुए 'जीएसटी 2.0' लागू करने का साहसिक निर्णय लिया है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए यह कदम आसान नहीं होता क्योंकि टैक्स में राहत का सीधा असर राजकोषीय संग्रह पर पड़ता है लेकिन मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार ऐसा करके यह संदेश दिया है कि जनता के हित उसके हर फैसले की धुरी हैं। यह दुर्लभ दृश्य है कि कम समय में दो-दो बड़े टैक्स सुधार लागू किए जाएं। पहले डायरेक्ट टैक्स में राहत और अब इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा बदलाव। यही वह नीति है जिसने मोदी सरकार को आम आदमी के बीच विश्वास का प्रतीक बना दिया है।

विपक्ष की आशंकाएं सच्चाई से कोसों दूर : विपक्ष हमेशा की तरह इस बार भी जनता के हित में लिए गए सरकार के इतने बड़े फैसले भी भ्रम फैला रहा है। विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ दरों का पुनर्गठन किया है और इससे वास्तविक सस्तीकरण नहीं होगा। जबकि सच्चाई यह है कि उपभोक्ता बाजार में पहले ही बदलाव दिखाई दे रहे हैं। दवा कंपनियां नई कीमतें घोषित कर चुकी हैं, बीमा कंपनियां कम प्रीमियम वाली योजनाएं पेश कर रही हैं और उपभोग वस्तुओं के ब्रांड्स ने MRP घटाने की घोषणाएं शुरू कर दी हैं। जहां विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, वहीं वास्तविकता यह है कि यह सुधार जनता की ज़िंदगी को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि टैक्स कलेक्शन की कमी को विकासशील क्षेत्रों और बढ़ी हुई मांग से पूरा किया जाएगा।

नवनीत सहगल
(अध्यक्ष, प्रसार भारती)

आम आदमी के जीवन पर सीधा असर : इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को मिलता दिख रहा है। पहले जहां दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर जहां 12 या 18 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता था अब वे पांच प्रतिशत या 0 टैक्स के दायरे में आ गई हैं। इसका असर रसोई से लेकर दवा की दुकान तक दिखने लगेगा। मोदी सरकार ने खाद्य पदार्थों में सीधी राहत दी है। पैकेज्ड पनीर जैसी चीज़ें अब पहले से सस्ती होंगी। इतना ही नहीं आम आदमी की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी सरकार ने सोचा। जीवनरक्षक दवाएं और कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं जीएसटी मुक्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को भी टैक्स से बाहर करने का फैसला हुआ है। घरेलू उपकरण जैसे टीवी, एसी जैसी रोज़मर्रा की बड़ी ज़रूरतें 28 से घटकर 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। ये कदम केवल राहत का प्रतीक नहीं बल्कि सरकार की उस नीतिगत सोच को भी दर्शाते हैं जिसमें 'जनता की जेब में बचत' को विकास का अहम आधार माना गया है।

उपभोग और मांग में बढ़ोतरी : टैक्स स्लैब घटने का असर सीधे उपभोग पर पड़ना तय है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मांग में तेज़ी आएगी और छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी कंपनियों तक को इसका फायदा मिलेगा। जहां विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ़ 'इधर से उधर' का खेल है, वहीं आंकड़े बताते हैं कि टैक्स घटने से रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वास्तविक कमी आ रही है। यही वजह है कि बाजारों में पहले ही रौनक लौटने लगी है और त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों में खरीदारी को लेकर उतसाह देखा जा रहा है।

पतन से प्रगति तक : पीएम मोदी कैसे गढ़ रहे हैं नया शहरी भारत ?

जालंधर ब्रीज : रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही नया शहरी भारत भी एक दिन में नहीं बनेगा। लेकिन जब हम अपने शहरों से और अधिक की अपेक्षा करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हम पहले ही कितनी दूरी तय कर चुके हैं? आजादी के दशकों बाद तक, भारत के शहर एक उपेक्षित विचार थे। नेहरू की सोवियत शैली की केंद्रीकृत सोच ने हमें शास्त्री भवन और उद्योग भवन जैसे कंक्रीट के विशाल भवन दिए, जो 1990 के दशक तक ही ढहने लगे थे और सेवा के बजाय नौकरशाही के स्मारक बनकर रह गए।

2010 के दशक तक दिल्ली की हालत बहुत खराब थी। सड़कों पर गड्ढे थे, सरकारी इमारतें पुरानी, बदरंग और टपकती छतों वाली थीं और एनसीआर की बाहरी सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता था। एक्सप्रेसवे बहुत कम थे, मेट्रो कुछ ही शहरों तक सीमित थी और बुनियादी ढांचा तेजी से टूट-फूट का शिकार हो रहा था। दुनिया का नेतृत्व करने का सपना देखने वाले देश की राजधानी उपेक्षा और बदहाल स्थिति का प्रतीक बन चुकी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात को बदल दिया। उन्होंने शहरों को बोझ नहीं माना, बल्कि उन्हें विकास के इंजन और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बनाया। यह बदलाव आज हर जगह दिखाई देता है। सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण ने कर्तव्य पथ को जनता की जगह बना दिया, नई संसद को भविष्य के अनुरूप संस्थान में बदल दिया और कर्तव्य भवन को सुचारु प्रशासनिक केंद्र बना दिया। जहां पहले जर्जर हालत थी, वहां अब महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास दिखता है।

इस बदलाव का पैमाना आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2004 से 2014 के बीच शहरी क्षेत्र में केंद्र सरकार का कुल निवेश लगभग ₹1.57 लाख करोड़ था। 2014 के बाद से यह 16 गुना बढ़कर लगभग ₹28.5 लाख करोड़ हो गया है। 2025-26 के बजट में ही आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को ₹96,777 करोड़ दिए गए, जिसमें एक-तिहाई हिस्सा मेट्रो के लिए और एक-चौथाई आवास के लिए रखा गया। इतना बड़ा वित्तीय निवेश स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और इससे अभूतपूर्व रूप से शहरी ढांचे का स्वरूप बदल रहा है।

हरदीप सिंह पुरी
(केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है)

भारत की व्यापक आर्थिक और डिजिटल प्रगति ने इस रफ्तार को और तेज कर दिया है। आज हम लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जहां डिजिटल व्यवस्था रोजमर्रा की जिंदगी को चला रही है। यूपीआई ने अभी हाल ही में एक महीने में 20 अरब लेन-देन का आंकड़ा पार किया और हर महीने ₹24 लाख करोड़ से ज़्यादा के लेन-देन संभाल रहा है। अब 90 करोड़ से अधिक भारतीय इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और 56 करोड़ जनधन खाते जैम त्रिमूर्ति (जनधन, आधार, मोबाइल) का आधार हैं, जिसके ज़रिये सब्सिडी सीधे और पारदर्शी रूप से दी जाती है। यह पैमाना, औपचारिकता और फिनटेक अपनाने का मॉडल पूरी तरह भारतीय है और इसका असर सबसे गहरा शहरी क्षेत्रों पर दिखाई देता है।

मेट्रो क्रांति जमीन पर हुए बदलाव को सबसे अच्छी तरह दिखाती है। 2014 में भारत में सिर्फ़ 5 शहरों में लगभग 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन चल रही थी। आज यह बढ़कर 23 से अधिक शहरों में 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है, जो हर दिन एक करोड़ से अधिक यात्रियों को ढोती है। पुणे, नागपुर, सूरत और आगरा जैसे शहरों में नए कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे सफ़र तेज़, सुरक्षित और प्रदूषण-रहित हो रहा है। यह सिर्फ़ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें लोगों का समय बचना, हवा का साफ़ होना और नागरिकों को करोड़ों घंटे की अतिरिक्त उत्पादकता मिलना शामिल है।

शहरी कनेक्टिविटी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। एनसीआर के जाम से भरे इलाकों को नई बनी यूईआर-II (दिल्ली की तीसरी रिंग रोड) से राहत मिल रही है, जो एनएच-44, एनएच-9 और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़कर पुराने जाम के बिंदुओं को आसान बना रही है। भारत की पहली क्षेत्रीय तेज़ यातायात प्रणाली—दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस (नमो भारत)—पहले ही बड़े हिस्से पर चल रही है और पूरा संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है, जिससे पूरा सफ़र एक घंटे से कम समय में तय होगा। ये तेज़ और एकीकृत परिवहन प्रणालियां नए भारत के लिए एक नई महानगरीय सोच को आकार दे रही हैं। एक्सप्रेसवे अब शहरों के बीच की आवाजाही का नया चेहरा बन रहे हैं। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे, दिल्ली- मेरठ एक्सेस-नियंत्रित कॉरिडोर और मुंबई कोस्टल रोड ने दूरी घटा दी है और बड़े वाहनों को शहर की गलियों से बाहर निकालकर हवा को साफ़ किया है। मुंबई में देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु अब टापू जैसे शहर को मुख्य भूमि से सीधे जोड़ता है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पश्चिम भारत में विकास का नया केंद्र बनने जा रही है।

समावेशन भी हमेशा प्राथमिकता में रहा है। पीएम स्वनिधि योजना ने 68 लाख से ज़्यादा रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी वाला कर्ज़ और डिजिटल सुविधा दी है, जिससे छोटे उद्यमियों को रोज़गार फिर से खड़ा करने और औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका मिला है।

भारत की डिजिटल क्रांति : परिवर्तन का एक दशक और भावी योजना

जालंधर ब्रीज : पिछले एक दशक में भारत में एक ऐसी डिजिटल क्रांति आई है जो असाधारण है। जो प्रक्रिया लक्षित प्रौद्योगिकीय अंतःक्षेपों की एक श्रृंखला के रूप में शुरू हुई थी वह अब एक व्यापक परिवर्तन के रूप में विकसित हो चुकी है, जो भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वाणिज्य, और देश के कोने-कोने में बसे किसानों और छोटे उद्यमियों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है।

अर्जुन राम मेघवाल
(केंद्रीय मंत्री)

यह यात्रा आकस्मिक नहीं थी। इसे भारत सरकार द्वारा ठोस नीति निर्धारण, अंतरमंत्रालयी सहयोग, और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया है। जब संबद्ध मंत्रालयों जैसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), कृषि मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयों ने बड़े पैमाने में ज़मीनी स्तर पर परियोजनाओं को पूरा किया, तो दूसरी ओर नीति आयोग ने अभिसरण को बढ़ावा देकर, विचारों को नेतृत्व देकर, और स्केलेबल, नागरिक-प्रमुखता वाले नवाचारों की ओर प्रणाली को प्रेरित कर नीति इंजन का काम किया है। जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी की शुरुआत के साथ इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। लगभग 55 करोड़ बैंक खातों के खोलने के साथ-साथ, करोड़ों लोगों को, जो पहले वित्तीय प्रणाली की पहुंच से बाहर थे, उन्हें अकस्मात बैंकिंग व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक पहुंच प्राप्त हुई है। ओडिशा के एक छोटे से गांव में पहली बार बिना बिचौलिए की सहायता से एक सिंगल मदर को कल्याणकारी लाभ सीधे उनके खाते में प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। उनकी कहानी भारत भर के करोड़ों लोगों की कहानी बन गई है। यह वृहद वित्तीय समावेशन आंदोलन वित्त मंत्रालय के समर्थन और आधार तथा मोबाइल पैठ की सक्षम सहायता से अगला कदमः एक वित्तीय-प्रौद्योगिकी विस्फोट का आधार बना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) ने भारतीयों के लेन-देन के तरीके में क्रांति ला दी है। किसी मित्र को पैसे भेजने के एक अनूठे तरीके के रूप में शुरू किया गया यह तरीका शीघ्र ही छोटे व्यवसायों, सब्ज़ी विक्रेताओं और गिग वर्कर्स की जीवनरेखा बन गया। आज, भारत में प्रति माह 17 बिलियन से अधिक यूपीआई के माध्यम से लेनदेन होते हैं, और यहाँ तक कि सड़क किनारे के विक्रेता वाले भी एक साधारण क्यूआर कोड के ज़रिए डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं।

इसी दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत के डिजिटल अवसंरचना के मुख्य तंत्र को धीरे-धीरे और निरंतरता से तैयार किया जा रहा है। भारतनेट जैसी परियोजनाओं ने दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुँचाया है, जबकि इंडिया स्टैक ने कागज़-रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित सेवाओं का ढाँचा तैयार किया। डिजी-लॉकर ने छात्रों को अपने प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में रखने, और ई-हस्ताक्षर ने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के लिए दूरस्थ प्रमाणीकरण प्रदान किया। डिजी-यात्रा एक अग्रणी पहल है जो चेहरे के पहचान की तकनीक का उपयोग करके निर्बाध, कागज़-रहित और संपर्क-रहित हवाई यात्रा को संभव बनाती है। यह त्वरित चेक-इन, बेहतर यात्री अनुभव और बेहतर हवाई अड्डे की क्षमता में सुधार सुनिश्चित करती है, साथ ही विकेंद्रीकृत पहचान प्रबंधन के माध्यम से डेटा गोपनीयता की सुरक्षा भी करती है। यह भारतीय विमानन के भविष्य की तैयारी और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये मात्र ऐप ही नहीं हैं - ये एक डिजिटल गणराज्य की आधारशिला हैं। डिजिटल गवर्नेंस ने भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के शुभारंभ के साथ बड़ी उछाल लगाई है। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए डिज़ाइन किए गए, जेम ने 1.6 लाख से अधिक सरकारी क्रेताओं को 22 लाख से अधिक विक्रेताओं से जोड़ा है - जिसमें महिला उद्यमियों और एमएसएमई की बढ़ती संख्या शामिल है। राजस्थान के एक छोटे हस्तशिल्प विक्रेता के लिए, इसका अभिप्राय सरकारी संविदाओं तक पहुंच प्रदान करना था जो पहले अकल्पनीय था।

पीएम मोदी ने भविष्य के अनुरूप शासन के लिए "कर्मचारी" से "कर्मयोगी" तक का खाका तैयार किया

जालंधर ब्रीज : देश लोक प्रशासन में सुधार के अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। अब न केवल अधिकारियों के प्रशिक्षण के तरीके बदल रहे हैं, बल्कि उनकी सेवा के मायनों में भी बदलाव आ रहा है। मिशन कर्मयोगी—लोक सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस बदलाव में इंजन की भूमिका निभा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच झलकती है। 25 वर्षों से अधिक समय तक सरकार चलाने और पांच दशकों से अधिक सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले श्री मोदी, व्यवस्थाओं के प्रति एक संचालक जैसी समझ, जड़ आदतों के प्रति एक सुधारक जैसी अधीरता, और ध्रुव तारे की तरह स्पष्ट —नागरिक-प्रथम, विकसित भारत के उद्देश्य को सामने रखते हैं।

मिशन कर्मयोगी की खासियत यह है कि यह केवल दिखावे भर के लिये मानव संसाधन सुधार नहीं है। यह देश की लोक सेवाओं की मूल्य-आधारित परिवर्तनकारी पुनर्रचना है और इसका मुख्य ध्यान प्रदर्शन पर है। यह कार्यक्रम तीन निर्णायक बदलावों को संहिताबद्ध करता है: पहला बदलाव सरकारी अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव है, यानी स्वयं को कर्मचारी मानने से लेकर कर्मयोगी मानने तक का सफर है।

दूसरा बदलाव कार्यस्थल में बदलाव है, इसमें प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी सौंपने से लेकर प्रणालीगत प्रदर्शन बाधाओं का निदान और उन्हें दूर करने तक का बदलाव शामिल है। तीसरा बदलाव सार्वजनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और उससे जुड़ी क्षमता निर्माण प्रणाली को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बनाना है। यह संरचना स्पष्ट रूप से मोदी के इक्कीसवीं सदी के शासन की मांगों के दूरदर्शी ढांचे से उभर कर सामने आयी है। यह जीवंत नेतृत्व का परिणाम है। मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी ने एक समग्र सरकारी संस्कृति को बढ़ावा दिया—अलग-अलग क्षेत्रों में अलगाव को खत्म किया, मंत्रियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बहस पर बल दिया, और फाइलों को आगे बढ़ाने की बजाय सिस्टम समाधानों को प्राथमिकता दी। यह भावना महामारी के दौरान दिखाई दी, जब सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और नागरिक स्वयंसेवकों के सभी स्तरों पर "टीम इंडिया" एक साझेदारी मॉडल के रूप में आगे बढ़ी। यही सहयोगात्मक शक्ति अब जीईएम और गतिशक्ति जैसे सुधारों को संस्थागत रूप दे रही है। उन्होंने नेतृत्व की आदतों को संरचनाओं में भी ढाला। जो चिंतन शिविर—आवासीय, पदानुक्रम-समतल विचार-मंथन सत्र—गुजरात में शुरू किए गए थे वे अब केंद्र सरकार की कार्यपुस्तिका का हिस्सा हैं। निरंतर सीखने पर उनका बल व्यक्तिगत है। अपने ज्ञान और कौशल का निरंतर विस्तार करने के अलावा, वे यह भी जांचने के लिए जाने जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी आईजीओटी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं। संस्थागत स्मृति के साथ उनके व्यवहार में बहुत समावेशीता है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, उन्होंने मंत्रियों से दशकों तक एक तरह से व्यवस्था से भली-भांति परिचित अपने सहायकों और अनुभाग अधिकारियों से सीखने का आग्रह किया। व्यवहार में संस्कृति परिवर्तन ऐसा ही दिखाई देता है। जमीनी स्तर पर, सुधार की रीढ़ उद्देश्यपूर्ण तकनीक है। आईजीओटी -कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म एक व्यापक, कभी भी और कहीं भी सीखने का ईको सिस्टम है। इसमें 3,000 से ज़्यादा स्व-प्रगति पाठ्यक्रम हैं जो सभी के लिए सुलभ हैं और सीखने को लोकतंत्रात्मक बनाते हैं। यह सीखने को मानव संसाधन कार्यों जैसे योग्यता मानचित्रण, करियर नियोजन और मार्गदर्शन से जोड़ता है—देश को प्रदर्शन पुलिसिंग से सक्षम क्षमता की ओर ले जाता है। यह पहले से ही बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदान कर रहा है। लाखों अधिकारियों को नए कानूनी ढांचों के अनुरूप प्रशिक्षित किया गया है; देश भर में लाखों पुलिस, डॉक्टर और अन्य कर्मचारी नागरिक संपर्क को मजबूत कर रहे हैं और सेवाभाव कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं; और बड़ी संख्या में लोग एआई और आईओटी जैसी उभरती तकनीकों में प्रमाणपत्र प्राप्त कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री की "तकनीक-अनुकूल" प्राथमिकता संस्थागत ताकत में परिवर्तित हो चुकी है।

डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम
(भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग के मानव संसाधन सदस्य)

केंद्रीय मंत्री ने पठानकोट के कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, मौके पर जारी किए निर्देश

कहा- पीएम मोदी बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की कर रहे निगरानी

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/पठानकोट

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में आई बाढ़ के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज पंजाब के पठानकोट जिले के कई गांवों का दौरा किया। पठानकोट के उपायुक्त आदित्य उप्पल और पुलिस अधीक्षक ढिल्लों के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम के साथ केंद्रीय मंत्री ने मौके पर ही कई निर्देश जारी किए, जिनका तुरंत पालन किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी संतुष्टि और खुशी हुई। केंद्रीय मंत्री ने पोला, कोहलियां और रावी नदी के तटवर्ती गांवों का दौरा किया। इसके अलावा, उन्होंने बामियाल, चाल, अमीर, सिम्बल सकोल, ढिंडा और भूपालपुर में रावी और जलाली नदियों के किनारे बसे इलाकों का भी दौरा किया। इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री को आपदा के दौरान हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी गई।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पंजाब के सभी 23 जिलों में चल रहे कार्यों की भी निगरानी कर रहे हैं और प्रभावित गाँवों का आज का दौरा इसी का एक हिस्सा है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्थानीय प्रशासन को पुलों जैसे क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की मरम्मत में तेज़ी लाने के निर्देश दिए और उन्हें जल्द से जल्द हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले अनुभवों से सीखते हुए, बनने वाले नए ढाँचों में पुलियों और पुलों की ऊँचाई और चौड़ाई बेहतर गुणवत्ता की होगी। मंत्री ने कहा कि पुनर्निर्माण की स्थायी व्यवस्था होने तक अस्थायी आश्रयों के माध्यम से पीड़ितों के पुनर्वास की तत्काल व्यवस्था की जा रही है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि जहाँ भी बाढ़ के पानी में ज़मीन बह गई है, वहाँ प्रशासन द्वारा ज़मीन की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। मंत्री ने बताया कि उन्होंने सोमवार को अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय टीमें पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये टीमें घरों, सड़कों, पुलों, फसल भूमि और अन्य बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान के स्तर पर भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगी। उन्होंने पंजाब और जम्मू-कश्मीर दोनों में प्रभावित आबादी के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

पठानकोट के बाढ़ प्रभावित गांवों के आज के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ लोक निर्माण विभाग, आरएंडबी, पीएचई और कृषि विभाग के अधिकारी, उपायुक्त आदित्य उप्पल और एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों भी मौजूद थे। उपायुक्त द्वारा बाढ़ पर साझा किए गए एक प्रेस नोट के अनुसार, उफनती रावी नदी कोलियन के पश्चिम में तटबंधों के एक बड़े हिस्से को बहा ले गई, जिससे कोलिया अड्डा के लगभग 700 निवासी प्रभावित हुए। लगभग 600 मीटर तटबंध बह गया। गुज्जर परिवारों के 35 घर बह गए। स्थानीय निवासियों के लगभग 30 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जिले की उप-तहसील नरोट जैमल सिंह के अंतर्गत आने वाले कोलिया गाँव के सामने स्थित अड्डा में लगभग 30 दुकानें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों सहित प्रात:काल गांव मंडाला छन्ना स्थित धुस्सी बांध का किया दौरा

बांध को और मज़बूत बनाने के लिए चल रहे कार्यों का लिया जायज़ा

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल ने गुरुवार प्रात:काल गांव मंडाला छन्ना स्थित धुस्सी बांध का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बांध को और मज़बूत बनाने के लिए चल रहे कार्यों का जायज़ा लिया और इस कार्य में दिन-रात जुटे जल निकासी व अन्य विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। डा.अग्रवाल ने कहा कि जल निकासी व अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, सैकड़ों स्वयंसेवक और समुदाय पिछले कई दिनों से बांध के संवेदनशील तट को मज़बूत बनाने और उसकी सुरक्षा

के लिए दिन-रात काम कर रहे है। इस दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि ज़िला प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के नेतृत्व में जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है और इस बांध को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। गौरतलब है कि सेना, एस.डी.आर.एफ., पुलिस की टुकड़ियां, श्रमिक, स्थानीय स्वयंसेवक और समुदाय के लोग बांध को और मज़बूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे है और प्रशासन व ड्रेनेज विभाग द्वारा अन्य जिलों से बड़ी संख्या में मिट्टी के बैग मंगवाकर यहां लगाए जा रहे है। हर स्तर पर योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है ताकि बांध को सुरक्षित रखा जा सके। दरिया का बहाव बांध की तरफ होने के कारण बांध की स्थिति संवेदनशील ज़रूर है, लेकिन बांध अभी भी खड़ा है।

किसानों को खेतों से रेत-सिल्ट हटाने की अनुमति : डीसी आशिका जैन

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण जिले के अनेक किसानों की कृषि भूमि पर सिल्ट, रेत व अन्य नदी जनित सामग्री जम गई है जिससे उनकी अगली फसल की बुआई प्रभावित हो सकती है। इस पर पंजाब सरकार ने किसानों के हित में "जेहदा खेत, ओहदी रेत" नामक विशेष, समयबद्ध योजना की घोषणा की है जिसके तहत किसानों को अपने खेतों से रेत, सिल्ट या नदी से आई अन्य सामग्री हटाने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा एक बार के लिए 31 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध

रहेगी और इसके लिए किसानों को किसी प्रकार का परमिट या विभागीय अनुमति (एनओसी) लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 के नियम 90 के तहत यह प्रावधान लागू किया है। डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी किसानों और जमींदारों को इस योजना की जानकारी व्यापक स्तर पर पहुंचाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेतों से रेत या सिल्ट हटाने की यह गतिविधि "खनन" की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि यह कदम किसानों को अगली बुआई के लिए भूमि तैयार करने में मदद करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में पारदर्शिता, तत्परता और जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए।

चीमा ने केपी के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया

कहा- दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। आज मॉडल टाउन स्थित पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के आवास पर पहुँचकर कैबिनेट मंत्री ने इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जवान बेटे के इस तरह चले जाने से परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है, ईश्वर परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर सहकारी कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष पवन कुमार टीनू और आप नेता राजविंदर कौर थियाडा भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के पुत्र रिची केपी की हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

अवतार नगर कॉलोनी में 75 लाख की लागत से बनेंगी सड़कें

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत और मेयर विनीत धीर ने सड़कों के गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा होने का आश्वासन दिया

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब के बागवानी एवं संरक्षण सेवाए कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत और मेयर विनीत धीर ने आज वार्ड नंबर 47 की न्यू अवतार नगर कॉलोनी में 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पार्षद मनमीत कौर भी उपस्थित थी। इस दौरान लोगों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल इस क्षेत्र में आवागमन आसान होगा, बल्कि स्थानीय लोगों और दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी। शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता को दोहराते हुए, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में विकास कार्य समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिदिन विकास कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है और इन परियोजनाओं के लिए फंड की कोई कमी नहीं है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए और भी सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर मेयर वनीत धीर ने कहा कि आने वाले दिनों में नगर निगम द्वारा और भी विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से शहर के विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा। अवतार नगर कॉलोनी के निवासियों ने नई सड़क परियोजनाओं की शुरुआत के लिए कैबिनेट मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कनेक्टिविटी में सुधार होगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी।

पंजाब विश्वविद्यालय में नुक्कड़ नाटक एवं स्वास्थ्य वार्ता का सफल आयोजन

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंचकूला स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने 10वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में "आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानेट" विषय पर नुक्कड़ नाटक और स्वास्थ्य वार्ता का सफल आयोजन किया। नुक्कड़ नाटक का मंचन पंजाब विश्वविद्यालय के स्टूडेंट सेंटर में बीएएमएस प्रथम प्रोफेशनल के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। नाटक का मुख्य संदेश पर्यावरण संरक्षण तथा आधुनिक युग में आयुर्वेद के महत्व पर केंद्रित रहा।

स्वास्थ्य जागरूकता वार्ता जीएच-4 कस्तूरबा छात्रावास में आयोजित की गई। इसका संयोजन डॉ. अनुराग कुशल (सहायक प्राध्यापक, पंचकर्म विभाग) एवं डॉ. आकांक्षा राणा (सहायक प्राध्यापक, रचना शरीर विभाग) ने किया। इसमें डॉ. बिंदु शर्मा (वार्डन एवं सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र विभाग) ने सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर डॉ. रितेश (सहायक प्राध्यापक, क्रिया शरीर विभाग) ने "हाइड्रेशन एवं आहार संबंधी आदतों पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण" विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। आयोजन का उद्देश्य आमजन को आयुर्वेद को दैनिक जीवन में अपनाने हेतु प्रेरित करना और समुदायों को समग्र स्वास्थ्य की प्राचीन भारतीय परंपरा से जोड़ना रहा। संस्थान ने इस आयोजन की सफलता पर माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा एवं अधिष्ठाता प्रोफेसर गुलाब पामनानी के प्रति आभार व्यक्त किया।

भ्रूण के लिंग की जांच करवाना या करना गैरकानूनी, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई : सिविल सर्जन

स्वास्थ्य विभाग जालंधर की ओर से जिला एप्रोप्रियेट अथॉरिटी (पीसी-पीएनडीटी) की बैठक

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

जिला एप्रोप्रियेट अथॉरिटी (पीसी-पीएनडीटी) की बैठक सिविल सर्जन कार्यालय जालंधर में चेयरपर्सन जिला एप्रोप्रियेट अथॉरिटी-कम-सिविल सर्जन डॉ. रमन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला एडवाइजरी कमेटी द्वारा सिफारिश किए गए 2 नए स्कैन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन संबंधी आवेदन तथा 8 स्कैन सेंटर्स की रिन्यूअल संबंधी आवेदन पर विचार किया गया। जिनमें से 2 नए स्कैन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन को दस्तावेज़ों की जांच के बाद मंज़ूरी दी गई और 8 स्कैन सेंटर्स के रिन्यूअल आवेदन को भी दस्तावेज़ों की जांच के बाद मंज़ूरी दी गई।

सिविल सर्जन डॉ. रमन गुप्ता ने कहा कि भ्रूण के लिंग की जांच करवाना/करना गैरकानूनी है और इस अपराध में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ज़िले में इस एक्ट को सख़्ती से लागू करने के लिए वचनबद्ध है और लिंगानुपात में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जालंधर जिले का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 939 लड़कियों का है। इसमें और सुधार लाने के लिए विभाग की नज़र लगातार अल्ट्रासाउंड स्कैन सेंटर्स पर है और उनकी नियमित चेकिंग की जा रही है। मीटिंग में शामिल सदस्यों को संबोधित करते हुए डॉ. गुप्ता ने कहा कि लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए मानसिक सोच बदलने की ज़रूरत है। भले ही पीसी-पीएनडीटी एक्ट लागू करने से लिंगानुपात में सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार लाने के लिए समाज की सोच में बदलाव जरूरी है। इस मौके पर एक्ट की उल्लंघना करके लिंग की जांच करने और करवाने वालों को दी जाने वाली सजाओं और जुर्माने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

इस अवसर पर डॉ. वरिंदर कौर थिंद (गायनी) एसएमओ, बच्चों के रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिनव शूर, सहायक जिला अटॉर्नी गगनदीप, लीगल प्रोबेशन ऑफिसर संदीप भाटिया, परवीन अबरोल (सोशल वर्कर), रमनप्रीत कौर (सोशल वर्कर), डिप्टी एमईआईओ असीम शर्मा, जिला पीसी-पीएनडीटी कोऑर्डिनेटर दीपक बपोरिया मौजूद थे।

डीसी द्वारा 3 नए आम आदमी क्लीनिकों का कार्य जल्द पूरा करने के आदेश

कपूरथला (जालंधर ब्रीज). डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल की अध्यक्षता में आज जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की मीटिंग हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने 8वें चरण के तहत खोले जा रहे 3 नए आम आदमी क्लीनिकों की समीक्षा करने के अलावा पंजाब सरकार द्वारा लोगों को दी जा रही मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) नवनीत कौर बल भी मौजूद थीं।

डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों को इन आम आदमी क्लीनिकों के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि नए शुरू किए जा रहे आम आदमी क्लीनिकों के कार्य की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करके इसे जल्द पूरा करवाया जाए, ताकि लोगों को उनके घरों के नजदीक आम आदमी क्लीनिक का लाभ मिल सके।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि बरसाती मौसम के दौरान लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके अलावा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के लिए घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए उपचार सुविधाएं हर जरूरतमंद तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में टॉप पर

फोटो-बीसीसीआई

स्पोर्ट्स डेस्क. आईसीसी ने अपन ताजा रैंकिंग जारी की है। जहां भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। दरअसल, टेस्ट में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं तो वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल टॉप पर काबिज हैं। इसके साथ ही टी20 में अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी तो गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर हैं।

टेस्ट में इंग्लैंड के जो रूट बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर उनके ही हमवतन हैरी ब्रूक हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग के टॉप 10 में भारत से सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं। यशस्वी जायसवाल 792 अंकों के साथ पांचवें र ऋषभ पंत 768 अंकों के साथ 8वें नंबर पर हैं। इसके अलावा टेस्ट में गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 के सिंहासन पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के कगीसो रबाडा हैं। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में बुमराह के अलावा कोई दूसरा भारतीय गेंदबाज नहीं है। मोहम्मद सिराज 15वें और रविंद्र जडेजा 17वें पायदान पर हैं।

वहीं वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर एक पर काबिज हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। विराट कोहली चौथे नंबर पर मौजूद हैं। टॉप 10 में गिल, रोहित और कोहली के अलावा श्रेयस अय्यर भी मौजूद हैं। वह 8वें नंबर पर हैं। वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग की बात करें तो, दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज नंबर वन पर बने हुए हैं। तो टॉप 10 में भारत के दो गेंदबाज कुलदीप यादव एक पायदान खिसकर चौथे पर मौजूद हैं तो रविंद्र जडेजा 2 पायदान खिसककर 10वें नंबर पर हैं।

टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो फिल सॉल्ट दूसरे और जोस बटलर तीसरे पर हैं। भारत के तिलक वर्मा चौथे पायदान पर हैं। सूर्यकुमार यादव 7वें नंबर पर हैं।

इसके अलावा टी20 गेंदबाजों में भारत के वरुण चक्रवर्ती नंबर एक पर हैं। वह पहली बार रैंकिंग में टॉप पर काबिज हुए हैं। उनके अलावा रवि बिश्नोई 8वें नंबर पर हैं। जबकि टेस्ट में रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। तो वनडे में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा टॉप पर हैं और अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। टी20 में भारत के हार्दिक पंड्या नंबर 1 ऑलराउंडर बने हुए हैं।

8 करोड़ की पुलियों के बनने से चंगर इलाके की 70 साल पुरानी समस्या होगी हल : बैंस

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/कीरतपुर साहिब

शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आज 18 सितंबर को तड़क्सार, हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बरसात ने इस इलाके को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज उन्होंने इलाके के गाँवों का दौरा किया, जहाँ सड़कों का नेटवर्क पूरी तरह टूट गया है। खड्डों में अधिक पानी आने के कारण लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और मरीज़ों को इलाज के लिए भी कठिनाइयाँ आ रही हैं।

बैंस ने कहा कि बीते कल ही दबूर में 1.01 करोड़ रुपये की लागत से पुल और दबूर अपर में 70 लाख रुपये की लागत से पुल बनाने की मंज़ूरी मिल चुकी है। इन दोनों पुलों का टेंडर अगले हफ्ते लगाया जाएगा। यह परियोजनाएँ चंगर इलाके के इन गाँवों की आवाजाही की 70 साल पुरानी समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगी। बैंस ने आगे बताया कि 8 करोड़ रुपये की लागत से पुलियों के निर्माण की भी मंज़ूरी हो चुकी है और इसका काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाके में अक्सर भारी बरसात के दौरान खड्डों में पानी आ जाता है। आज तड़क्सार में हुई भारी बरसात के कारण मांगेवाल, दबूर और लोहड़ खड्ड में पानी के अधिक बहाव से फसलों और पशुधन को भारी नुकसान पहुँचा है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.